साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 20 | प्रति सोमवार इंदौर, 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

तीनों प्रदेशों की सार्वजनिक संपत्तियों की लूट व नीलामी

इवीएम की जालसाजी : 3 राज्यों में थोपे 3 कठपुतली मुख्यमंत्री

शपथ लेते ही सारी विद्युत कंपनियां अदानी के हवाले कर दी 'डकैत मोदी' ने

नवंबर 23 में हुए तीन बड़े-बड़े राज्यों के चुनावों में इवीएम की जालसाजियों से जो सत्ता हड़पी गई इसका मूल उद्देश्य यही था, की सारे पुराने न केवल मुख्यमंत्रियों मंत्रियों और सारे जाने वाले चेहरों को नेपथ्य में ढकेल दिया जाए।

यह किया भी गया जितने तीनों प्रदेशों में नेताओं ने 30-40 साल से जो अपनी मेहनत की थी। पार्टी को लगातार धरने प्रदर्शन रथ यात्रा बाबरी कांड आदि कर जनता की निगाहों में चढ़ा जनता को जोड़कर शून्य से शिखर तक उठाकर सत्ता के शीर्ष पर ले गए थे। उन सब नेताओं को जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी यशवंत सिंहा, सुब्रण्यं स्वामी को पीछे धकेल जो ज्यादा साफ छवि के बुद्धिमान नेता शक्तिशाली थे। जिन में सुषमा स्वराज अरुण जेटली अनिल माधव दवे मोहन परिकर आदि की चिकित्सीय हत्या करवा दी गई। ताकि उन जाहिल चांडाल अपराधियों मोदी और अमित शाह को देश को लूटने बर्बाद करनेऔर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने में कोई और रास्ते में बाधक न बने और उसे इसी बीच उसने देश के अधिकांश कोयला खदानें न केवल अदानी को सौंप दी। बल्कि स्टेट बैंक से 26000 करोड़ रुपए का लोन अदानी को दिलवाकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की खदान ली गई अब देश का कोयला जो 5 से रु. 7000 टन बिकता था। अब वही कोयला विदेशी कोयले के नाम पर रु. 30000 टन बेंचने के साथ कोयले की कीमतों के नाम पर जनता से बिजली की कीमत बढ़ाकर लूटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे मोदी ने तेल बेल सेल रेल मेल जेल गेल हाल बैंकों बीमा कंपनियां हीरे तांबा अभ्रक आदि कीमती पदार्थों की जिसकी खदानी मध्य प्रदेश में है से लेकर यूरेनियम लिथियम आदिकी खदानें छत्तीसगढ़ में हैं। गेल और ओएनजीसी जो राजस्थान के मरुस्थल में पेट्रोल निकलते हैंवह खजानेभी अब इन तीनों नए मुख्यमंत्री जो 10-12 साल पुराने नेता हैं। मुख्यमंत्री बनकर लूटने का षड्यंत्र कर दिया गया क्योंकि तीनों नए हैंतो स्वागत है उनको सत्ता चलाने का अनुभव भी नहीं और चुकी अचानक उनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया है। तो जिसने सौंपा है वह आपराधिक आका जैसा कहेंगे उनको नाचना मजबूरी हो जाएगी और अभी आसन्न लोकसभा चुनाव में पुनःसारे मोहरे अपने बैठा कर इवीएम की जालसाजियों से पुनः सत्ता हथियाना का षड्यंत्र करने में कोई बड़ा ना बने इसलिए उसने तीनों अपनी कठपुतली मुख्यमंत्रियों को तीनों राज्य में बैठाकर अब भाई प्रदेश की सारी सड़कों को अदानी को नीलाम कर देगा पहले उसमें जनता का लूटा हुआ पैसा निर्माण में 5से 10 गुना ज्यादा कीमतों पर निविदायें लगा और देकर उसे काम दिया जाएगा और फिर उसे काम में समय विस्तार और महंगाई की लागत वृद्धि देकर कई गुना भुगतान किया जाएगा बदले मेंतीनों राज्यों की जनता को सड़कों पर चलने का प्रति किलोमीटर 10 से 25 रुपए तक टोल टैक्स देना पड़ेगा। (शेष पेज 6 पर)

सभी विभागों में भर्तियां करो, वर्तमान में 20% स्टाफ

20 वर्षों में शिवराज ने पूरे प्रदेश के शासकीय ढांचे को खत्म कर दिया पुनः भर्तीयां व पदोन्नतियां दे पुनः तंत्र को मजबूत करो।

प्रदेश को 20 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मिला पिछले लगभग 20 सालों में सभी विभागों में सेवा निवृत्ति, मृत्यु और एच्छिक सेवा निवृत्ति के कारण अधिकांश विभागों में मात्र 20% स्टाफ रह जाने के कारण एक ही कर्मचारी अधिकारी के पास चार-चार, पांच-पांच प्रकार के प्रभार हैं। इसलिए अति महत्वपूर्ण कार्यों इसमें शिक्षा स्वास्थ्य प्रशासन श्रम लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, गृह निर्माण मंडल, गृह, न्याय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग पशु चिकित्सा ग्रामीण एवं पंचायत ग्रामीण यांत्रिकीय, नगर निगमों पालिकाओं, खनिज, निर्वाचन, वन, नर्मदा घाटी, वाणिज्य कर राजस्व, आदि सभी विभागों में जो पिछले 8 साल से प्रभार वसूल कर प्रभार देने का खेल किया जा रहा है इसको तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। सभी को नियमित पदोन्नतियां दी जाएं। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन का सवाल है तो वह स्थगन जिन्हें 2002 के बाद से10 तक पदोन्नतियां दे दी गई थी उनको पुनः पदोवनत न करने के लिए दिया गया था ना की पदोन्नतियां रोकने के लिए।

दूसरी तरफ इस सिक्के का पहलू यह भी है। की सभी पदोन्नतियों के पत्र जारी करते समय लिखा जाता है कि यह निश्चित नियमों व शर्तों के अधीन दिया जा रहा है इसमें कोई बदलाव होने पर परिवर्तन किया जा सकता है। जब यह वाक्य जोड़ा ही जाता है तो पदोन्नतियां देने में कहां कोई स्थगन व नियम बाधक बन रहा है। जिसके कारण 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों का पिछले 8 साल से लगातार प्रभार देने के नाम पर परिवार वसूलने और मासिक कल्टमर सुनने का षड्यंत्र किया जा रहा है जो यथार्थ में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है दूसरी तरफ शासन के सभी विभागों में 20 साल से लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर्स व अन्य पदों पर ठेका कर्मी और संविदा कर्मियों की जो रुपए 8 से 10000 महीने से लेकर डॉक्टर इंजीनियरों की रु. 25000 महीने पर भर्तीयां व नियुक्तियां ठेका कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं। आखिर क्या कोई मुख्यमंत्री मंत्री अपनी जेब से पैसा दे रहा है बेशक इसमें भारी षड्यंत्र हैं जिन कर्मचारियों की 30 50 हजार वोट तनखा निकलती है उन्हें 8-10 हजार रुपए महीने पर रखकर बीच का पैसा हजम कर लिया जाता है (शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

देश पूरे तौर पर जंगली राज और कंगाली का शिकार

चले थे विश्वगुरु बनने, हो गए कटोरे के कंगाल

हर मुख्य विश्व के सूचकांक में आखिरी पायदान पर देश पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान से भी तुलना मुश्किल

राष्ट्रीय स्तर पर देश की जड़ों को खोदने वाले नरेंद्र मोदी भाजपा की कब्र खोद रहे हैं जिनके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाना भाजपा के लिए आसमान के तारे तोड़ लाने जैसा ही हो जायेगा। हो सकता है अभी यह बात लोगों को हजम न हो लेकिन लक्षण ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति ने जीवन के साथ ही मृत्यु का बीज भी रख दिया है। सभी जीव-जंतु जीते हुए क्रमशः मौत की ओर बढ़ते चले जाते हैं; यह शाश्वत सत्य है। मोदी भक्त में अंधभक्ति के दौरे पड़ने कम हो गये हैं, देश का माहोल देखने से साफ पता चलता है। लोग समझने लगे हैं कि उन्हें दो-तीन चुनींदा देश को लूटने वाले पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ कर प्रोपेगैंडा-तंत्र के जरिए झूठ परोसकर रामनाम और हिन्दुत्व के नाम पर अंधकार में धकेला जा रहा है। वे देख रहे हैं कि सत्तालोलुप मोदी - शाह देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पूरी तरह गुंडे-मवालियों, फ्रॉड, बलात्कारीओ और अपराधियों की शरणास्थली बन चुकी है। वहां अब एक भी भला आदमी नहीं है। एक से बढ़कर एक भ्रष्ट, लफंगे, फ्रोड़ अनैतिक, कभी भी अनाप-शनाप बक देने वालों से यह पार्टी भरी हुई है। जनता को खुलेआम धमकाया जा रहा है कि यदि उसे वोट नहीं दिया तो राज्य को दंगों की आग में झोंक दिया जाएगा। आम आदमी देख रहा है कि विकास तो जैसे भाजपा के एजेंडे में कहीं है ही नहीं। ऊपर से देश में लोकतंत्र को लगातार कमजोर किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सामाजिक समरसता को लगातार कमजोर किया जा रहा है। जनसरोकारों को भुलाकर भाजपा अपनी मातृसंस्था RSS का एजेंडा लागू करने के एकसूत्री अभियान में जुटी हुई है। यदि भाजपा जनता के एक भी मुद्दे पर संसद, मीडिया और उसके बाहर कोई बात नहीं करती और बड़ी चालाकी से दूसरों को भी विषय से भटका देती है तो फिर दो-तीन भ्रष्ट धनपशुओं के अलावा इसकी जरूरत किसे है। कुछ लोगों का मानना है कि **RSS** - भाजपा अगले वर्ष ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर हिंदुओं के वोट बटोरने में कामयाब हो जायेगी तो यह सिर्फ एक कल्पना है क्योंकि आम हिंदू वर्ष में एकाध बार ही खास मौकों पर मंदिर जाता है, अन्य दिनों में वह अपनी रोजी-रोटी तथा अन्य कामों में ही व्यस्त रहता है। उसे अयोध्या या किसी भी अन्य मंदिर से कोई लेना-देना नहीं होता। उसकी जिंदगी जिन बातों से प्रभावित होती है उसमें मंदिर का कोई स्थान नहीं है। आधुनिक समाज आस्था के बहाने सत्ता पर कब्जा करने की चालबाजी को समझता है तो वह अपनी रोजी-रोटी और अमन-चैन को प्राथमिकता देता है। वर्तमान मनुष्य के आगे भूख मिटाने और शांति से जीवनयापन करने से बड़ा सवाल या लक्ष्य कुछ भी नहीं है। आखिरकार बिना भोजन भूखे पेट कोई कब तक भजन कर सकता है? इस सवाल का कोई जवाब **RSS** -भाजपा के पास नहीं है। और यही इनकी असफलता का कारण है। जो यही साबित करता है कि तथाकथित धर्म की हांडी बार-बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। धर्म की कोरी लफ्फाजी सुनते-सुनते लोगों के कान पक गये हैं। उन्होंने अब इस तरह के प्रोपेगैंडा पर ध्यान देना उसी तरह बंद कर दिया है।

न्यायाधीश साहसी बने रहें

सर्वोच्च न्यायालय की सेवा से रिटायर होने वाले न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल का यह कहना भारतीय लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूती देने वाला है कि न्यायाधीशों को बेधड़क होकर बिना किसी बेखौफ-ओ-खतर के निष्पक्ष फैसले करने चाहिए क्योंकि उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिला होता है। हमारे लोकतन्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके महत्वपूर्ण स्तम्भ न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतन्त्र रखा गया है और राजनैतिक दलों की बनने वाली सरकारों के प्रभाव से इसे अलग रखते हुए सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपना दायित्व पूरा करने का कार्यभार सौंपा गया है। श्री कौल आगामी 25 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं और 18 दिसम्बर से सर्वोच्च न्यायालय के 2 जनवरी तक के लिए जाड़े की छुट्टियां हो रही हैं। रिटायर होने से पूर्व पारंपरिक विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चन्द्रचूड की मौजूगी में न्यायमूर्ति कौल ने ये विचार व्यक्त करके साफ कर दिया कि यदि मौजूदा शासन प्रणाली में न्यायाधीश ही अपना कार्य बिना किसी पक्षपात और खौफ के नहीं करेंगे तो शेष प्रशासकीय ढांचे से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः जजों या न्यायाधीशों को 'दिलेर' या 'साहसी' होना चाहिए।

श्री कौल के मत में न्यायाधीशों का साहसी होना पूरे प्रशासनिक तन्त्र की निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी होता है। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश मंडली में श्री कौल की प्रतिष्ठा अत्यन्त विशिष्ट व गौरवमयी मानी जाती है। उन्होंने जितने भी निर्णय दिये उनमें उनके निष्पक्ष व्यक्तित्व की झलक भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कश्मीर के अनुच्छेद 370 समाप्त करने के पक्ष में उनके दिये गये फैसले में भी यह छाप दिखाई पड़ती है।

उन्होंने अपने फैसले में 370 को समाप्त किये जाने के हक में फैसला देते हुए यह भी लिखा कि जम्मू-कश्मीर राज्य में नागरिकों पर हुई कथित ज्यातियों की जांच के लिए एक 'सत्य व सान्त्वना आयोग' को भी गठित किये जाने की जरूरत है। वैसे अगर गौर से देखा जाये तो स्वतन्त्रता के बाद भारत की न्यायपालिका का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और गरिमामय रहा है केवल अपवाद के रूप में इमरजेंसी के 18 महीने के कार्यकाल को जरूर देखा जा सकता है। देश की इस सबसे बड़ी अदालत के न्यायमूर्तियों में समय पड़ने पर देश के लोकतन्त्र की मजबूती के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी और अपने पद के स्तर को हमेशा निष्पक्ष बनाये रखने के लिए सामूहिक इस्तीफे तक दिये हैं।

जैसा कि 1974 में केन्द्र की इन्दिरा गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक कनिष्ठ न्यायाधीश श्री अजितनाथ राय को मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठाने के विरोध में चार न्यायमूर्तियों ने इस्तीफे दे दिये थे। इस घटना ने भी देश के लोकतन्त्र प्रेमियों को प्रेरणा देने का कार्य बहुत भीतर तक किया था। इससे पूर्व 1969-70 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने लोकप्रिय जन अवधारणा की परवाह न करते हुए केवल संविधान और कानून की कसौटी पर इन्दिरा सरकार द्वारा 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण व राजा- महाराजाओं के प्रिविपर्स उन्मूलन के सरकारी फैसलों को भी अवैध करार दे दिया था। हालांकि इन्हीं मुद्दों पर 1971 में हुए लोकसभा चुनावों में इन्दिरा जी की पार्टी कांग्रेस की महाविजय हुई थी और बैंक राष्ट्रीयकरण व प्रिविपर्स उन्मूलन का विरोध करने वाली पार्टियों जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, संसोपा व संगठन कांग्रेस के चौगुटा गठबन्धन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बाद में संविधान संशोधन करके ही ये दोनों फैसले लागू किये गये थे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कई और ऐतिहासिक फैसले दिये जिनमें संविधान के मूल ढांचे को न बदलने का निर्णय शामिल है।

भारत के लोकतन्त्र को सर्वदा जीवन्त व कानून परक बनाये रखने के लिए और संविधान निर्माताओं के दूरदृष्टि मूलक फैसलों को हर काल में सामयिक बनाये रखने का यह निर्णय बहुचर्चित गोलकनाथ मामले में दिया गया था। इसके अलावा महाराज सिंह भारती मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण का मुकदमा भी मील का पत्थर बना हुआ है। सच तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की स्वतन्त्रता के पिछले 76 सालों में 'अभयदीप' बन कर लोकतन्त्र के दो अन्य खम्भों विधायिका व कार्यपालिका को दिशा दिखाने का काम करता रहा है। देश की राजनीति बदलने का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और यह संसद द्वारा बनाये गये कानूनों को भी संविधान की कसौटी पर कस कर उन्हें वैध या अवैध घोषित करता रहा है।

न्यायपालिका की मुख्य चिन्ता पूरे भारत में संविधान का शासन देखने की रही है और यह कार्य हर दौर में उसने पूरी मुस्तैदी के साथ किया है। जहां तक निचले स्तर की न्यायपालिका का सवाल है तो इसकी कार्यप्रणाली में विशेष कर आपराधिक मुकदमों के सन्दर्भ में इसमें बहुत सुधारों की जरूरत 60 के दशक से ही महसूस की जाती रही है। इसकी तरफ पहली बार इशारा स्व. चौधरी चरण सिंह ने 1969 में तब किया था जब उन्होंने इस वर्ष अपनी नई पार्टी 'भारतीय क्रान्ति दल' बनाई थी और इनके घोषणापत्र में 'कोर्ट-कचहरी' के कामकाज में प्रशासनिक व न्यायिक सुधारों की बात लिखी थी। इन सुधारों की गूंज हमें अब 52 साल बाद भी सुनाई पड़ रही है जिसे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड ही करते हुए दिख रहे हैं। अतः न्यायमूर्ति कौल के कथन को व्यापक सन्दर्भों में देखने की आवश्यकता है।

संवैधानिक संरक्षण परोक्ष रूप से हमारी कार्यपालिका को भी मिला होता है क्योंकि हर जिले का जिलाधीश और पुलिस कप्तान भी संविधान की शपथ ही लेता है। मगर उसे राजनैतिक नेतृत्व के निर्देशन में काम करना पड़ता है। इसकी वजह से कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं जिनका सम्बन्ध सीधे राजनीति के 'स्तर' और राजनीतिज्ञों के "चरित्र" से जाकर जुड़ता है।

धुँआ धुँआ संसद, धुँआ धुँआ हुआ सारा देश

तानाशाही के सितम से उबलते बहके, हताश, निराश व कुण्ठित युवाओं के हाथों धुँआ धुँआ हुई संसद है और झूठ, झाँसा, धोखा, छल, कपट व ठगाई के अन्धकार वाली सत्ता की जुल्मी नियत और जालिमी नीतियों की बेईमानी के गुब्बारों से रिसते धुँधलकों से धुँआ धुँआ हुआ सारा देश है, जघन्य हत्यारों, बलात्कारियों और महानतम भ्रष्टाचारियों की पूजा से हर रोज़ धूप बत्ती से फैलता धुँआ, अतीव धर्मान्धता का धुँआ, नफ़रत की घृणा की ज़हरीली आँधी का धुँआ, धार्मिक उन्माद का धुँआँ, मारकाट का घातक धुँआ, झूठी देशभक्ति व छद्म राष्ट्रवाद की धोखे से भरी इसी ठगाई की भारी धोखेबाज़ी में फँसकर धुँआ धुँआ हुआ सारा देश है,

कश्मीर आतंक में जल रहा है, फ़ौजी अफ़सरों की लाशों पर आए दिन देश शोक में डूब रहा है, मणिपुर शमशान बना धर्मांधता की रक्तपात की आँधी में सरघट हुआ जा रहा है और चीन चार हज़ार वर्ग किलोमीटर पर क़ब्ज़ा कर बैठा है हमारे आका चीन के हित में पुंगी बजाते बैठ गए हैं कायरता की पाँति में, संसद की तरह सीमाओं की सुरक्षा भी धुँआ हुई है और इसी असुरक्षा के भय की आशंका में डूबता धुँआ धुँआ हुआ सारा देश है, भीषण मँहगाई, भयानक बेरोज़गारी, ज़बरदस्त मुद्रास्फीति, अतीव भूखामरी, कुपोषण, भयावह भ्रष्टाचार, आर्थिक ग़ैर बराबरी, आर्थिक लूटपाट, आर्थिक उत्पीड़न, आय व कमाई मे निरन्तर भारी गिरावट, क़ीमतों की बढ़ती हिमालयी रफ़्तार से घर घर फैली भारी कंगाली, मुफ़लिसी, शोषण, सरकारी टैक्स व लूट की बर्बादी

के धुँए से लादी तबाही से धुँआ धुँआ हुआ सारा देश है, चुनाव आयोग का तिकड़मी किन्तु पालतू सत्तापक्षी धुँआ, चुनावी मशीनरी का छोड़ा अपूर्व फ़ितरती धुँआ, सरकारी एजेन्सियों के आतंक का धुँआ अब इन सारे के सारे भयों से भयातुर होता जन जन ही नहीं अब तो धुँआ धुँआ हुआ सारा देश है.

- सोहन मेहता 'क्रान्ति'
जोधपुर, राजस्थान

अधिकांश नेता मंत्री उप मुख्यमंत्री स्पीकर भी खनन माफिया

खनन से खनका रहे मोटी कमाई

बिन्दु – 18 निविदाओं आदि से संबंधित जानकारी
– विभागीय पोर्टल ई-खनिज पर Advertisement & Tender Section में उपलब्ध है।
अनुसूची चार के गौण खनिजों का ई-निविदा
द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी ई-निविदा के परिणाम

क्र.	निविदा क्रमांक / दिनांक	जिला तहसील ग्राम	खसरा नम्बर रकबा (हे.)	खनिज	आरक्षित मूल्य (रु. प्रति टन)	प्राप्त उच्चतम निविदा (रु.प्रति टन)	उच्चतम निविदाकार का नाम	LOI जारी करने का दिनांक
1	1(1) 18.10.21	कटनी [illegible]	339 4.430 हे.	डोलोमाइट	105	750	मेसर्स [illegible]	02.02.2022
2	1(2) 18.10.21	कटनी [illegible]	75, 88 13.036 हे.	[illegible]	84	280	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	02.02.2022
3	1(3) 18.10.21	कटनी [illegible]	89 10.190 हे.	लेटेराइट	84	282	[illegible] इंदौर, म.प्र.	02.02.2022
4	1(4) 18.10.2021	कटनी [illegible]	188 27.130 हे.	लेटेराइट	84	333	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	02.02.2022
5	1(5) 18.10.21	कटनी [illegible]	115, 117 2.173 हे.	लेटेराइट	84	288	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	02.02.2022
6	1(6) 18.10.21	कटनी [illegible]	119, 118, 111 3.600 हे.	लेटेराइट	84	288	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	02.02.2022
7	1(7) 18.10.21	कटनी [illegible]	396, 612 20.030 हे.	लेटेराइट	84	352	[illegible] इंदौर, म.प्र.	02.02.2022
8	1(8) 18.10.21	[illegible]	184 2.702 हे.	डोलोमाइट	105	258	मेसर्स [illegible] इंदौर, म.प्र.	02.02.2022
9	1(9) 18.10.21	[illegible]	498 9.600 हे.	लेटेराइट	84	180	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	02.02.2022
10	2(1) 28.03.22	[illegible]	2811, 2842 5.902 हे.	लेटेराइट	84	340	श्री [illegible]	05.08.2022
11	2(2) 28.03.22	[illegible]	429 21.030 हे.	लेटेराइट	84	166	श्री [illegible]	05.08.2022
12	2(3) 28.03.22	[illegible]	109 27.140 हे.	लेटेराइट	84	215	श्री [illegible]	05.08.2022
13	2(4) 28.03.22	[illegible]	2038 6.600 हे.	[illegible]	50	2186	श्री [illegible]	05.08.2022
14	2(5) 28.03.22	[illegible]	389 16.710 हे.	[illegible]	50	1160	श्री [illegible]	05.08.2022
15	2(6) 28.03.22	[illegible]	517, 518 4.900 हे.	[illegible]	111	180	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	05.08.2022
16	3(1) 20.05.22	कटनी [illegible]	9 [illegible] 13 [illegible] 14 [illegible] 3.42 हे.	डोलोमाइट	105	1060	मेसर्स [illegible]	23.09.2022
17	3(2) 20.05.22	[illegible]	846 4.700 हे.	लेटेराइट	84	600	मेसर्स [illegible]	23.09.2022
18	3(3) 20.05.22	[illegible]	863 15.430 हे.	लेटेराइट	84	500	मेसर्स [illegible]	23.09.2022
19	3(4) 20.05.22	[illegible]	1/1 5.223 हे.	लेटेराइट	84	500	मेसर्स [illegible]	23.09.2022
20	3(5) 20.05.22	[illegible]	54 9.32 हे.	लेटेराइट	84	321	श्री [illegible]	23.09.2022
21	3(6) 20.05.22	[illegible]	839 4.002 हे. [illegible]	[illegible]	111	202	मेसर्स [illegible] कटनी, म.प्र.	23.09.2022
22	3(10) 20.05.22	[illegible]	[illegible] 799 4.002 हे.	डोलोमाइट	105	402	[illegible]	23.09.2022
23	3(11) 20.05.22	[illegible]	[illegible] 799 6.600 हे.	डोलोमाइट	105	521	श्री [illegible]	23.09.2022
24	3(12) 20.05.22	[illegible]	[illegible] 589 6.602 हे.	डोलोमाइट	105	511	श्री [illegible]	23.09.2022
25	4(1) 19.09.22	कटनी [illegible]	694, 697 3.110 हे.	लेटेराइट	84	632	श्री [illegible]	28.11.2022
26	4(2) 19.09.22	[illegible]	4 1.800 हे.	डोलोमाइट	105	1200	मेसर्स [illegible]	28.11.2022
27	4(3) 19.09.22	[illegible]	254 14.691 हे.	डोलोमाइट	105	1200	मेसर्स [illegible]	28.11.2022
28	4(4) 19.09.22	[illegible]	76 3.100 हे. [illegible]	[illegible]	111	201	श्री [illegible]	28.11.2022
29	4(5) 19.09.22	[illegible]	76 4.000 हे. [illegible]	[illegible]	111	201	श्री [illegible]	28.11.2022

गौण खनिज रेत की ई-निविदा द्वारा जिला रेत समूहों के ठेका हेतु जारी ई-निविदा के परिणाम

क्र	निविदा क्रमांक / दिनांक	जिला तहसील ग्राम	आरक्षित मूल्य (रुपये प्रति घनमीटर)	प्राप्त उच्चतम निविदा (रुपये प्रति घनमीटर	उच्चतम निविदाकार का नाम	आशय पत्र जारी दिनांक
1	40, दिनांक 06/01/22	शिवपुरी	250	630	राज [illegible] श्री [illegible] गुप्ता	04/03/2022
2	01/08/2022	भिंड	250	265	सुनील सिंह भदौरिया	25/08/2022
3	04/08/2022	ग्वालियर	250	265	सुनील सिंह भदौरिया	05/09/2022
4	09/08/2022	नरसिंहपुर	250	328.30	श्री [illegible] सिंह	08/09/2022
					मझौली	
5		सिंगरौली	250		मेसर्स शर्मा एसोसिएट्स बीजिका टॉवर, वार्ड नंबर 8, [illegible], [illegible], जिला नरसिंहपुर।	07/10/2022
6	1692 17/11/2022	बैतूल	250	567	मेसर्स [illegible] एण्ड सर्विसेज लिमिटेड	23/12/2022
7		पन्ना	250			
8		बुरहानपुर	250	315	मेसर्स [illegible] प्रो. श्री [illegible]	19/12/2022
9	1658 20/09/2022	सिवनी	250	277.40	श्री [illegible] पाठक	16/11/2022

बिन्दु – 19 विभागीय जानकारी निरंक है

बिन्दु – 20 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

स्थानांतरण नीति म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाती है। विभाग की पृथक से कोई स्थानांतरण नीति नहीं स्थानांतरण आदेश e-khanij.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु – 21 आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण

वर्ष 2022 में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक 156 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 150 का निराकरण किया गया।

बिन्दु – 22 सीएजी और पीएसी पैरा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरिक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्षो की जानकारी

क्र0	प्रतिवेदन वर्ष	कंडिकाओं की संख्या
1.	2012–13 राजस्व क्षेत्र क्रमांक–01	11
2.	2015–16 राजस्व क्षेत्र क्रमांक–5	04
3.	2016–17 राजस्व क्षेत्र क्रमांक–01	14
4	2017–18 राजस्व क्षेत्र क्रमांक–02	16
5	2019–20 राजस्व क्षेत्र क्रमांक–06	34

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन लंबित

क्र0	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन क्रमांक	भारत के नियंत्रक का वर्ष रिपोर्ट वर्ष	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन वर्तमान में लंबित है।
1.	89 वां (चतुर्दश)	2006–07	विधानसभा में लंबित
2.	386 वां (चतुर्दश)	2009–10	विधानसभा में लंबित
3.	390 वां (चतुर्दश)	2010–11	विधानसभा में लंबित
4.	393 वां (चतुर्दश)	2011–12	विधानसभा में लंबित
5.	471वां (चतुर्दश)	2013–14	विधानसभा में लंबित
6.	नवम् वां (पंचदश)	2014–15	विधानसभा में लंबित

जिलाधीश, खनिज अधिकारी व निरीक्षक घोर भ्रष्ट व जालसाज इसलिये सूचना अधिकार में जानकारी नहीं...

मध्य प्रदेश में कीमती खनिज हीरों से लेकर तांबा अभ्रक चूना कोयला तक उपलब्ध होने के साथ-साथ भवनों, सड़कों के निर्माण में गिट्टी पत्थर मोरम रेती जो कि हर जिले व उसकी आसपास की नदियों में पाई जाती हैं। के पट्टे देने खनन को संरक्षण देने में यही राजस्व के पटवारी राजस्व, खनन निरीक्षक, मौका मिलने पर पुलिस निरीक्षकों से लेकर जिला अधिकारियों कलेक्टर तक हर जिले में अरबों रुपए प्रति वर्ष का भ्रष्टाचार करते हैं। छोटे पट्टे ले लिए दिये जाते हैं फिर महीना बांधकर खनन ठेकेदारों के साथ मिलकर कई गुना ज्यादान केवल रेती, गिट्टी, पत्थर से लेकर सभी कीमतीखनिजों कादोहन कर मोटी कमाई की जाती है और उसमें सभी सरकारी कर्मचारी निरीक्षकों अधिकारियों कामहीना लेकर अंत सहयोग किया जाता रहता हैसरकार ने व्यवस्थाएं काफी बदली है परंतु पूर्व का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानी प्रदेश का सबसे बड़ा रेती माफ़िया था वर्तमान में जो उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला व स्पीकर को बनाया गया है जिनमें काफी वीडियो चले यह भी प्रदेश के जाने-माने खनन माफिया हैं।

मोहन सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन

रेत माफिया पर पहली बार चला बुलडोजर

मध्य प्रदेश की नई मोहन यादव सरकार ने शपथ लेते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है. पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के यहां बुलडोजर चलाया और अब रेत माफिया के घर पर बुलडोजर चला दिया है. नर्मदापुरम में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई की है. बता दें कि नर्मदापुरम जिले के पांजराकलां ग्राम में दो दिन पहले अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपियों नायाब तहसीलदार कीर्ति प्रदान और माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें प्रशासन द्वारा बुलाए गए प्राइवेट ट्रैक्टर चालक पत्थर लगने से घायल हो गया था. इस मामले में आज आरोपी रेत माफिया के घर पर प्रशासन की टीम पहुंची और बुलडोजर से मकान ध्वस्त कर दिया. कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अमले ने ग्राम मेहराघाट स्थित आरोपी सोनू निमोदा और मयंक निमोदा के मकान का अवैध हिस्सा जेसीबी से ढहा दिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 5 बजे नयाब तहसीलदार कीर्ति प्रदान जमीन का सीमांकन कार्य समाप्त कर लौट रही थी. इस दौरान रास्ते में पांजरा में रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली जा रही थी. अधिकारी की गाड़ी को देख ड्राइवर ट्राली को छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया. इस दौरान नायब तहसीलदार ने माइनिंग इंस्पेक्टर पिंकी चौहान और कृष्णा परस्ते को मौके पर बुला लिया था. ट्राली ले जाने के लिए प्राइवेट ट्रैक्टर के ड्राइवर छुट्टू गोस्वामी को बुलाया गया. ट्राली में जैसे ही ट्रैक्टर को जोड़ रहे थे तभी आरोपी सोनू निमोदा, मयंक निमोदा वहां आए और उन्होंने राजस्व और माइनिंग विभाग की टीम पर पथराव कर हमला कर दिया. पथराव में ड्राइवर छुट्टू गोस्वामी के सिर में पत्थर लगा.

ट्रैक्टर चालक को लगा था पत्थर

आनंद-फानन में महिला अधिकारी ने अमले के साथ ड्राइवर को अपनी गाड़ी से शहर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. नायब तहसीलदार ने देहात थाने पहुंचकर आरोपी मयंक निमोदा और सोनू निमोदा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कराया था. देहात थाना पुलिस ने रेत चोरों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. इसके बाद आज आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मकान के हिस्से को ढहाया है.

अवैध रूप से किया जा रहा था परिवहन

नर्मदापुरम एसडीएम आशीष पांडे ने बताया कि 14 तारीख को पांजरा कला में ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ने के संदर्भ में एक घटना घटित हुई थी. उसके पश्चात फिर हुई. उसमें जो प्रमुख आरोपी थे उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था. उसमें अवैध निर्माण को हटाया गया है. आरोपी सोनू और मयंक निमोदा ग्राम मेहराघाट है. अभी घटना को लेकर कार्यवाही की गई है आगे भी जैसे निर्देश मिलेंगे कार्रवाई करते रहेंगे.

साप्ताहिक समय माया

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को प्राप्त आवेदन
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक)

क्र	विषय	जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक	अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022	योग
1	घरेलू अत्याचार	67	223	290
2	दहेज प्रताड़ना	117	384	501
3	पारिवारिक विवाद	70	151	221
4	बलात्कार	35	132	167
5	बलात्कार का प्रयास	8	52	60
6	अपहरण	23	95	118
7	दहेज हत्या	06	32	38
8	हत्या	14	61	75
9	आत्महत्या	04	11	15
10	महिला प्रताड़ना / महिला देह व्यापार / दैहिक शोषण	170	535	705
11	कार्यस्थल प्रताड़ना / मानसिक प्रताड़ना / यौन शोषण	56	299	355
12	संपत्ति विवाद	55	163	218
13	भरण पोषण	05	14	19
14	बच्चों से संबंधित	04	3	07
15	साइबर अपराध	07	19	26
16	विभागीय प्रकरण	38	67	105
17	पुरुष प्रधान	29	67	96
18	हिंसा	04	17	21
19	मारपीट	51	232	283
20	अन्य	146	613	759
	योग	909	3170	4079

जनवरी 2019 से अब तक आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण कार्यरत (Functional) नहीं होने से आवेदनों के निराकरण हेतु बैठों का आयोजन तथा आवेदनों पर सुनवाई कर निराकरण की प्रक्रिया बाधित रही। शासन के निर्देशानुसार जनवरी 2019 से अब तक की अवधि में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। फलस्वरूप दिसम्बर 2022 तक लगभग 13 हजार आवेदन निर्देशानुसार अग्रेषित किए गए जिनमें से 50 प्रतिशत आवेदनों के प्रतिवेदन भी कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/संबंधित विभाग के अधिकारियों से आयोग को प्राप्त हो गए हैं।

महिला बाल विकास रू. 15 हजार करोड़ खर्च, रू.7 हजार करोड़ हजम

मप्र सरकार से बच्चे तक कुपोषण की चपेट में...

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 23 में महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के लिए बजट के में अनुपूरक पुनर्विनियोजन एवं समर्पण को समाहित करते हुए कुल राशि 695519.42लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध 14 फरवरी 2023 तक कुल राशि 312715.10 लाख का व्यय किया गया।

केंद्र द्वारा 13 योजनाओं में लगभग 4 से 5000 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने जैसा कि ऊपर बजट में लिखा हुआ है लगभग 3100 करोड रुपए खर्च किए जाते हैं यथार्थ में जितने भी भ्रष्ट ऊपर से लेकर नीचे तक प्रधान सचिव दीपावली रस्तोगी से लेकर नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक सब घर भ्रष्ट लुटेरों का अड्डा बन चुका है एक आंगनवाड़ी में औसतन 100 बच्चे भोजन करते हैं तो 98000 आंगनबाड़ियों में मध्य प्रदेश के लगभग 98 लाख बच्चे भोजन करने आते हैं। तो 7 करोड़ की आबादी में यह बताइए कि घरों में बच्चे किसके बच्चे भोजन करते हैं जबकि सच यह है, की 80% बच्चे अपने घरों में भोजन करते हैं। पर आंगनबाड़ियों में यह फर्जीवाड़ा आज से नहीं पिछले 30 साल से लगातार चल रहा है जहां मात्र 2-5% बच्चे आंगनबाड़ियों में भोजन करने आते हैं बाकी सब का भोजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से लेकर एकीकृत बाल विकास योजना अधिकारी से जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त संचालक महिला बाल विकास अधिकारी से लेकर प्रधान सचिव और मंत्री तक सारा पैसा बंटता है। अधिकांश योजनाओं का पोषण आहार का पैसा मुख्यालय से जिलों को आवंटित अवश्य किया जाता है। मुख्यालय में ही मोटे कमीशन वाला होने के कारण वह पोषण दलिया व अन्य सामग्री वहीं से आपूर्ति की जाती है। जिसका पैसा माल बाजार में

आंगनवाड़ी सेवाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश के सभी 313 विकासखण्डों में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इन बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। क्षेत्रवार परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	क्षेत्रवार परियोजना का प्रकार	परियोजना संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या
1	ग्रामीण	278	51558	8430
2	आदिवासी	102	24004	4013
3	शहरी	73	8903	227
	कुल	453	84465	12670

आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत हितग्राही

क्र.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या (लाख में)
1	2017–2018	120.00
2	2018–2019	124.00
3	2019–2020	139.00
4	2020–2021	92.47
5	2021–2022	90.05
6	2022–2023	90.58

प्रगति

दिनांक 15 फरवरी 2023 तक कुल प्राप्त सहयोग रुपये 25.80 करोड़

विवरण	लाभान्वित संख्या	पूर्ण कार्य का अनुमानित लागत
अधोसंरचना मूलक कार्य	15549 कार्य	रुपये 6.13 करोड़
बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता	557776 (लाभान्वित बच्चे)	रुपये 8.56 करोड़
स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा	48047 (लाभान्वित बच्चे)	रुपये 89.04 लाख
भोपाल एवं इंदौर में जनसहयोग से प्राप्त राशि		रुपये 8.41 करोड़
भोपाल एवं इंदौर में जनसहयोग से प्राप्त खिलौने का अनुमानित मूल्य		रुपये 1.01 करोड़
	योग	25.80 करोड़

कार्यक्रम का सोशल आडिट

कार्यक्रम में जन सहभागिता बढ़ाने तथा प्राप्त सहयोग राशि कार्यों के उपयोग में पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन पर निगरानी हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों का सोशल आडिट महिला एवं बाल विकास की सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है।

98 हजार आंगनवाड़ी में 98 लाख बच्चों का पोषण आहार, तो 80% घरों में कौन बच्चे भोजन करते हैं?

बेंच कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा हजम कर लिया जाता है। और उसका हिस्सा सबको बंटता है यही कारण है की आंगनवाड़ियों से लेकर जिला मुख्यालय व संचालक कार्यालयमें लगभग 24 योजना में हजारों करोड़ का धन कागजों पर खर्च करके हजम कर लिया जाता है। और सूचना का अधिकार का आवेदन लगाने पर भी जब सारा काम कंप्यूटर पर होता है। तो यह हरामखोर अपनी साइटों का यूआरएल का पता क्यों नहीं देते। इनकी साइटों पर अधिकांश जानकारी होने के बाद में वह साइट है। जो सार्वजनिक स्तर पर खुलता नहीं। संयुक्त संचालक कार्यालय में आवेदन देने पर वहां की जानकारी मांगने पर वहां बैठी हरामखोरों की फौज जो है आवेदन यह कर लौटा देती है कि हम जिम्मेदार नहीं है जबकि यथार्थ में होना यह चाहिए की मूल आवेदन को अंतरित करना चाहिए। संयुक्त संचालक कार्यालयों में भी अधिकांश मक्कार हरामखोर अय्याशों की फौज बैठी होती है। जो अधिकांश समय यहां वहां छोटे-मोटे काम करके मटरगश्ती करती रहती है और सूचना के अधिकार में जानकारी देने पर वस्तुओं की फौज नई-नई दलीलें सुनाया व जवाब में लिखा करती है यह हाल न केवल इंदौर उज्जैन बल्कि पूरे प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक कार्यालयों का है। जबकि इनका कार्य सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों पर नियंत्रण करना देखने करना वह आंगनवाड़ियों से लेकर हर कार्यक्रम की निरीक्षण करने का होता है यह निरीक्षण रिपोर्ट देने में भी इसलिए मोटर लगता है कि भ्रष्टाचार की कलई खुल जाएगी।

महिला बाल विकास प्रमुख सचिव दीपावली रस्तोगी, आयुक्त महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले, अपर संचालक सीमा ठाकुर, महिला बाल विकास राजपाल कौर, आरपी रमन बाल, एकीकृत बाल विकास परियोजना पीके से

केंद्र शासित योजनाएं

- आंगनवाड़ी सेवाएं (समेकित बाल विकास परियोजना)
- पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन),
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
- पोषण आहार,
- पोषण आहार शासन निर्देश,
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल,
- वन स्टॉप सेंटर,
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
- समेकित बाल संरक्षण योजना,
- राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना स्वाधार योजना,
- कामकाजी महिला छात्रावास,
- कार्यालय में महिलाओं का यौन उत्पीड़न,
- जेंडर बजट सेल चार्टर

राज्य शासित योजनाएं

- लक्ष्मी योजना,
- अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य व पोषण मिशन
- लाडो अभियान
- शौर्य दल मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना,
- मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम,
- उदिता योजना,
- लालिमा योजना,
- स्वागतम लक्ष्मी योजना
- उषा किरण योजना,
- घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना,
- लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010

वित्त सलाहकार संयुक्त संचालक शिवकुमार शर्मा, सुरेश सिंह तोमर, आरपी सिंह, अमिताभ अवस्थी, डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी, तृप्ति त्रिपाठी, डॉक्टर विशाल नाडकर्णी, स्वर्णिमा शुक्ला।

बजट–एक समग्र विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2022–2023 में महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के लिये मूल बजट में अनुपूरक, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण को समाहित करते हुऐ कुल राशि रुपये 695519.42 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध 14 फरवरी 2023 कुल राशि रुपये 312715.10 लाख का व्यय किया है।

विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 में क्रमशः कुल राशि रुपये 522206.42 लाख, 538573.17 लाख एवं रुपये 695519.42 लाख का बजट अनुपूरक, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण सहित प्रावधानित हुआ है। जिसके विरुद्ध क्रमशः रुपये 481999.54 लाख, रुपये 483554.47 लाख एवं रुपये 312715.10 लाख (14 फरवरी 2023 तक) व्यय किये गये जो निम्न चार्ट से स्पष्ट है –

वित्तीय वर्ष 2020–2021 से 2022–2023 (14 फरवरी 2023 तक की स्थिति में) तक योजनावार प्रावधानित एवं व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

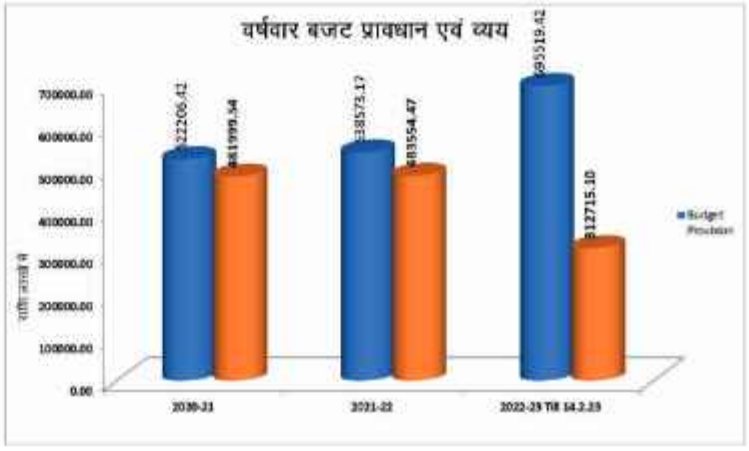

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी

राशि लाखों में

योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14.2.23 तक की स्थिति में कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14.2.23 तक की स्थिति में कुल व्यय
658	आंगनवाड़ी सेवा योजना	117093.02	106644.89	118250.02	102300.36	219540.17	136640.93
830	किशोर न्याय अधिनियम [illegible] के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन	30.10	1.83	27.60	8.73	18.13	5.63
854	राष्ट्रीय झूलाघर योजना	100.00	72.49	518.50	195.73	100.00	0.00
1071	महिला हेल्पलाइन 181	49.97	0.00	0.07	0.00	80.00	0.00
1268	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	304.00
1280	म.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	50.00	24.70	692.49	680.00	194.00	73.42
1291	आई.सी.डी.एस. के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्तर में सुधार की परियोजना ISSNIP / NNM	8156.10	4758.57	16745.92	14600.00	18554.60	10126.60
1326	स्वाधार गृह	250.00	121.62	250.00	141.16	250.00	0.00
1327	वन स्टाप सेंटर सखी	0.01	0.00	0.01	0.00	1661.24	0.00
1485	[illegible]	250.40	178.44	199.66	124.65	199.66	73.84
2367	महिला शक्ति केन्द्र	21.84	0.00	1430.02	0.00	1202.00	0.00
2375	जेंडर सिटी कार्यक्रम	174.50	59.53	174.51	119.63	174.50	0.00
3457	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला सशक्तिकरण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	90.93	42.64	90.93	35.89	90.00	61.26
5028	[illegible] योजना ([illegible] योजना)	50.01	16.71	150.01	51.82	150.01	21.05
5060	बाल भवन की स्थापना	409.20	324.71	435.66	330.40	444.95	299.37
5067	लाडली लक्ष्मी योजना	153579.52	136362.17	112153.22	106801.84	92554.23	9549.14
5360	आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण	3776.02	5053.89	9000.00	8990.02	11114.00	7148.22
5586	महिला बाल विकास के भवनों का रखरखाव	1.70	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	[illegible] का भवन निर्माण	500.00	100.00	324.00	318.65	323.98	6.73
5843	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	87041.28	86689.23	89341.25	84764.44	87041.26	59103.54
5869	मुख्यमंत्री [illegible] पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5827	बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन	258.14	201.57	271.21	176.99	293.57	188.40
6103	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	6754.20	5495.59	7516.22	6830.45	11594.63	2928.98
6390	किशोरी बालिका योजना	768.40	689.65	4499.98	0.00	0.19	0.00
6443	अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन	7.40	7.30	0.03	0.00	1552.02	2.71
6917	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना(पी.एम.एम.वी.वाई)	16760.84	14319.11	19627.33	12729.99	38860.60	9297.64
7300	[illegible] पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
7449	[illegible] प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	0.01	0.00	1352.02	0.00	1352.02	0.00

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय की योजनावार जानकारी

राशि लाखों में

योजना कोड	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14.2.23 तक की स्थिति में कुल बजट प्रावधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोजन/समर्पण सहित)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14.2.23 तक की स्थिति में कुल व्यय
7703	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
7854	पोषण अभियान 2.0	0.00	0.00	0.03	0.00	0.20	0.00
8052	किशोर कल्याण निधि योजना	10.00	0.00	100.00	0.00	460.00	0.00
8681	राज्य महिला आयोग का गठन	300.53	234.22	316.03	218.11	337.28	187.66
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	4.06	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8807	मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना	0.00	0.00	648.40	556.90	818.40	668.30
9041	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	12141.45	11736.40	13515.72	11761.21	14868.39	11738.17
9050	[illegible] कार्यक्रम [illegible] योजना	115606.54	110677.54	140902.22	129714.47	127724.84	60807.70
9446	आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3343	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	8401.14	3475.34
3888	लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान)	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00
3801	घरेलू हिंसा से पीड़ित के लिये सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	541.75	8.47
3824	महिलाओं के लिये [illegible] आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
3822	मिशन शक्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
3846	मिशन वात्सल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
9847	सक्षम आंगनवाड़ी पोषण -2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00
	महायोग महिला एवं बाल विकास	522206.42	481999.54	538573.17	483554.47	695519.42	312715.10

साप्ताहिक समय माया

इवीएम की जालसाजी : 3 राज्यों में थोपे 3 कठपुतली मुख्यमंत्री

पेज 1 का शेष

आपने देखा 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव का शपथ ग्रहण हुआ। उसी दिन शाम होते-होते पूर्व, मध्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पूरे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति और वसूली व्यवस्था सौंप दी गई।जो जो की पूर्व के मुख्यमंत्री उसको देने तैयार नहीं थे साथ ही स्मार्ट मीटर जो10 गुना ज्यादा तक विद्युत खपत दिखती है और बिल की वसूली करती है और स्मार्ट मीटर में अब लाइनमैन को लाइन काटने खंभे पर नहीं आना पड़ता, अब बिल जमा ना होने पर सीधे ही विद्युत संयोजन डबल एल एल जीपीएस सिस्टम से ही कंप्यूटर से काट दिया जाता है। यह उपलब्धि ईवीएम की जलसा जी का कमाल अब पूरे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दिखाएगी क्योंकि वहां की भी सारी विद्युत वितरण कंपनियां अब अदानी को सौंप दी जाएगी।

यह तो कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा था अब जितने भी शिक्षण संस्थान जनता के पैसे से सरकारी स्तर परचलाई जा रहे थे अब उनमें भारती आना होने परेशानी खर्च बढ़ाने का हवाला देकर उन शिक्षण संस्थानों को भी इन चांडलो को सौंप दिया जाएगा यही हाल सभी गांवों के स्वास्थ्य के दो से लेकर जिला अस्पतालों चिकित्सा महाविद्यालय तक को निजी क्षेत्र में सौंपने का और उसे मोटी कमाई लाखों करोड़ में करने का भी इन तीनों पैदल मुख्यमंत्री के माध्यम से संपन्न कर दिया जाएगा और जनता जो बेचारी गरीबी रेखा के नीचे स्तर पर जी रही है और उसके पास बेरोजगारी के कारण दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है उन 100 करोड लोगों को उन्होंने अगले 5 साल तक रु.1 किलो का गेहूं रु.2 किलो का चावल खिलाने का आश्वासन तो दे ही दिया है। तो जो जिम्मेदारी निशुल्क शिक्षा सड़क पीने के पानी स्वास्थ्य की सरकार की थी वह सब सीधे उसके वह चांडाल नीच मित्र गौतम अडानी और उसके गिरोहों को सौंप दी जाएगी। पर यह सब कुछ बहुत छोटी कहानी का हिस्सा है कहानी तो जो अब शुरू की जाने वाली है जिसके लिए कोरोना जैसा तांडव किया गया था वह यह है कि सारे छोटे लघु व घरेलू उद्योगों मंडियों बाजारों को खत्म कर लगभग तीनों प्रदेशों में जिनकी आबादी लगभग 20 करोड़ है। की 2 करोड लोगों को बेरोजगार कर सारा व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कंपनी को शॉपिंग मॉल को सौंपने का षड्यंत्र किया जाएगा। और उसकी अगली कहानी मेंडेस लोकसभा के चुनाव से पहले अगर हमारी नपुंसक नकारा जनता और उसके विपक्ष के सभी मक्कार डरपोक राजनीतिक दलों के विशेष रूप से कांग्रेस के नेता नेताओं ने जागकर अगर सड़कों पर धरने प्रदर्शन नहीं कियातो पुनः एवं के चुनाव से यदि लोकसभा जीत ली जाती है तो सारे देश के लगभग 30 करोड़ किसानों की भूमि को छुड़ाकर वॉलमार्ट अडानी अंबानी टाटा बिरला के साथ अमेजॉन देशी विदेशी कंपनियों को भी बेचने का षड्यंत्र तैयार है। जो पुरानी कृषि कानून किसानों के सतत आंदोलन के कारण रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें पुनर लघु कर देश की 70% आबादी को भिखारी बनाने का संरक्षण किया जाएगा यह सूअर अंध भक्तों को तो कभी समझ में नहीं आएगा पर ये मक्कार डरपोक निकम्मे कांग्रेसी नेता जो हैं। पूरे देश में एनी क्वेश्चन को पर निकाल को बाहर निकालकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर सबको बहाने का आंदोलन करना ही पड़ेगा। अनूठा भिखारी बनने के लिए तैयार रहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य यह है, कि उसको जैसा डराओगे धमकाओगे और पूरे छत्तीसगढ़ से खनिज संपदा के साथ मानव निर्मित संपदाओं जिसमें अनेकों पीएसयू इसमें एनटीपीसी, बालको, जिसे भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भिलाई स्टील प्लांट आदि अपने मित्र अदानी को बेचने के लिए सीधे-साधे आदिवासी को बैठाकर सब आसानी से हड़प लिया जाएगा।

जब भी कोई बात उठेगी या आदिवासी आवाज उठाएंगे जमीनों के लिए जंगल के लिए, नदियों के पानी के लिए, खनिजों के लिए, आदिवासी होने से मानव निर्मित एवं प्राकृतिक संपदा को अडानी की हवाले करने के लिए आवाज उठायेंगे तो बोल दिया जाएगा कि आपका आदिवासी मुख्यमंत्री ही सब कर रहा है।

नए सरकारों के अहम फैसले

तीन राज्य, तीन सीएम, तीन फैसले, जानें किसकी क्या प्राथमिकता

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तीनों राज्यों, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी तरह से बदल गई। इन मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कौन से अहम फैसले लिए। और इसके परिणाम क्या हुए? आइए जानते हैं विस्तार से।

एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद बाद एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने खुले में मांस की बिक्री, खुले में अंडे की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों से लेकर दूसरे सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर भी बैन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों द्वारा इसका पालन ना करने पर जुर्माने लगाने के आदेश भी दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लिए ये फैसले

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद प्रथम कैबिनेट की बैठक में किसानों और गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बैठक में कृषक उन्नत योजना, धान खरीदी, पीएम आवास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्य सचिव और सभी सचिव मौजूद रहे। बता दें कि कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दे दी गई है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि, ये हमारा चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान कहा था कि, बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला फैसला आवास योजना का लेंगे। अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा।

भजनलाल शर्मा ने लिए तीन बड़े फैसले

राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बीते शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने पहली बैठक में ही तीन बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया।

बता दें कि भजनलाल शर्मा की पहली बैठक में पेपर लीक, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं तक जनता की पहुंच को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल, पिछली सरकार में राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद राजस्थान चुनाव में पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं बीजेपी चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर रही है। अब शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ लने के बाद राज्य में पेपर लीक मामलों में एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है।

सभी विभागों में भर्तियां करो, बर्तमान में 20% स्टाफ

पेज 1 का शेष

जबकि उन बेचारे कर्मचारियों के भुगतान कई बार ठेकेदार लेकर भाग जाता है दूसरी तरफ उस भुगतान में से ठेकेदार को ठेका देने वाले अधिकारियों से लेकर भुगतान करने वाले कर्मचारियों कोभी भुगतान देकर उन ठेका कर्मियों का वेतन निकलवाने के साथ उसे पर 18% की जीएसटी भी देनी पड़ती है। जिसका भुगतान यथार्थ में उन ठेका वह संविदा कर्मियों को ही अपने अल्प वेतन में से भारी बेरोजगारी व मजबूरी के कारण करना पड़ता है। उसे पर भी नए मुख्यमंत्री को तत्काल रोक लगा कर अपने ही प्रदेश की जनता के शोषण को तत्काल रोकना चाहिए। निमित्त भारतीय करने से उन परसरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के सभी नियम और कानून लागू होने के कारण उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी जिससे शासन मेंबूढ़ा जलसा जिया और बहू रुपए की की जा रही है वह रोकी जा सकेंगे दूसरी तरफ स्वाभाविक सी बात है जो ठेका संविदा कर्मी अभी अपने आप को अत्यधिक असुरक्षित समझते हैं नियमित होने पर नियमित वेतनमान सुविधा मिलने के कारण ज्यादा जिम्मेदारी बहुत समय प्रभाव से अपनी सेवाएं शासन की सभी विभागों में दे सकेंगे अन्यथा तो ठेका व संविदा कर्मियो में महिलाओं के यौन शोषण से लेकर हर प्रकार का शोषण जिसमें उच्च अधिकारी उनसे ज्यादा जी पूर्ण कार्य करवा भ्रष्टाचार कर लेते हैं। और पकड़े जाने पर सारा खेल उनका स्थाई थे का वह सम्मेलन कर्मियों पर डालकर बचने का प्रयास करते हैं नजर आ रहे हैं हर विभाग में जिसे तत्काल रुक जाना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि सभी ठेका हुआ संविदा कर्मियों को जिनका चाल चलन और कार्य अच्छा है उन्हें नियमित कर उनकी सेवाएं लेनी चाहिए।

शायद नए मुख्यमंत्री मोहन यादव इन सब बातों पर गहराई से चिंतन कर सभी विभागों में कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रभारों से मुक्त कर नियमित पदोन्नतियां देंगे। और शीघ्र छवि विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की भर्ती करेंगे।

पालिकायें, निगम व पुलिस का उद्देश्य जनता को हैरान कर लूटना....

पेज 8 का शेष

पर मध्य प्रदेश में उसका 10 गुना वसूलकर भी जनता को वाहन चालकों को लूटने के साथ-साथ सड़कों पर भी जिस तरह से लूटा जा रहा है उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है सबसे पहले आवश्यक है कि सड़कों की चौड़ाई उनकी बनावट के साथ सड़कों की समय पर मरम्मत हो। परंतु जब यहां पर तो उद्देश्य ही कभी सुरक्षित नंबर प्लेट के नाम, कभी वाहन 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हो गए हैं। इसलिए उनको हटाया जाएगा जबकि नगर निगम पालिकाओं स्वयं शासन के अनेकों विभागों में उनके ही वाहन जो लाखों किलोमीटर चलने के बाद में भी 40 50 साल के बाद में उपयोग किया जा रहे हैं। उन पर कोई बंदिश नहीं और सरकारों पर अगर बंदिश लगाकर उनको हटाएगी तो वहां पर भी उसका उद्देश्य मोटे कमीशन पर नए वाहन खरीद कर जनधन को बर्बाद करना ही होगा। दूसरी तरफ मोटे कमीशन के चलते सरकार सड़कों से 15 वर्ष से ज्यादा वाहन हटाने के लिए बार- बार घोषणा करती है जबकि स्वयं सरकार वायु सेवा में 80 साल पुराने रूस का मिग 21 का 60 साल से उपयोग कर रही है। उसके बारे में चुप है तो यह दोहरी लूट वाली नीति क्यों? जितनी भी सड़कें वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग डकौती प्राधिकरण बना रहा है। उसमें सड़कों पर चलने का शुल्क प्रति लीटर डीजल पेट्रोल खर्च होने से ज्यादा महंगा कारों पर और चार पहिया वाहनों पर ठोका जा रहा है। जो रु.5 किलोमीटर से लेकर रु. 15 प्रति किलोमीटर तक कारों पर ट्रैकों और बसों पर रु.10 से रु.50 तक वसूला जा रहा है। संवैधानिक मूलभूत आवश्यकताओं में सरकार को निशुल्क सड़क शिक्षा बिजली पानी स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए थी। वर्तमान में सरकार जो पूर्व की केंद्र सरकार 250 से ज्यादा वस्तुओं व सेवाओं पर विक्रय बनाम वेट लगाया जाता था। वर्तमान में 1500 से ज्यादा वस्तुओं वह सेवाओं पर कर ठोक कर लूट जाने के बाद में भी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सुफ्त नहीं दे पा रही जबकि वहीं पेट्रोल पर जो रु. 20 लीटरभारत सरकार को पड़ता है उसे पर वह रु. 90 कर वसूल कर लेती है। इसके बाद में भी ना तो वह अच्छी सुरक्षित सड़क दे पाती है। तो आखिर यह जिम्मेदारी किसकी और फिर सरकार वह उसमें बैठे निरीक्षक सिपाही कर्मचारी अधिकारी संकेतकों का स्वयं तरीके से प्रबंधन करते नहीं जनता को परेशान करने जनजन की नीयत से कहीं 50 सेकंड कहीं 60 सेकंड तक चौराहा पंजराहों, षटराहों पर हरे संकेतक रखती है। जिससे दूसरे पथ वालों को ढाई सौ से 300 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता हैजो की यातायात पुलिस की बदतमीजी और लूट का खुला खेल होता है जिसे शीघ्र जाना चाहिए जब सड़के अच्छे हो ज्यादा संकेत का प्रबंध अच्छा हो इसके बाद भी यदि कोई लाल संख्या तक को पार करने की कोशिश करें तभी उसका अनुज्ञप्ति पत्र जिसकी केंद्र सरकार ने हिमाचल रु.200 शुल्क रखी है राज्य सरकार ढाई हजार रुपए लेने के साथ क्योंकि परिवहन कार्यालय में अधिकांश काम दलालू और ठेकेदारों से होता है रु.5000 तक लग या वसूले जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है की सरकार अपने स्तर पर सबसे पहले सड़क सुधारे। सुरक्षित अच्छी चौड़ी सड़कों का निर्माण वह रख-रखाव करें। उसके बाद वाहन चालकों को अनुज्ञप्ति रद्द करने की गलती करने पर घोषणा करें।

हनुमान जी को शिवजी का ग्यारहवां अवतार माना जाता है। हिन्दू मान्यतानुसार रुद्रावतार भगवान हनुमान माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी की जन्मतिथि पर कई मतभेद हैं लेकिन अधिकतर लोग चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही हनुमान जयंती के रूप में मानते हैं। हनुमान जी के जन्म का वर्णन वायु- पुराण में किया गया है।

हनुमान जयंती के दिव्य और अचूक टोटके

हनुमान जी की पूजा हनुमान जयंती के दिन प्रातः काल सभी नित्य कर्मो से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में चन्दन, केसरी, सिन्दूर, लाल कपड़े और भोग हेतु लड्डू अथवा बूंदी रखने की परंपरा है।

हनुमान जयंती के टोटके विशेष फल प्रदान करते हैं। हनुमान जयंती का दिन हनुमानजी और मंगल देवता की विशेष पूजा का दिन है। यह टोटके हनुमान जयंती से आरंभ कर प्रति मंगलवार को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस युग में हनुमानजी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी गई है।

- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा हनुमान जयंती के दिन और बाद में महीने में किसी भी एक मंगलवार को करने से आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
- हनुमान जयंती पर और बाद में साल में एक बार किसी मंगलवार को अपने खून का दान करने से आप हमेशा दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।
- 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का एक माला जाप हनुमान जयंती व मंगलवार को करना शुभ होता है।
- 5 देसी घी के रोट का भोग हनुमान जयंती पर लगाने से दुश्मनों से मुक्ति मिलती है।
- व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती को सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमानजी को पहनाइए।
- हनुमान जयंती पर मंदिर की छत पर लगाइए लाल झंडा और आकस्मिक संकटों से मुक्ति पाइए।
- तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

हनुमान भगवान शिवजी के ११वें रुद्रावतार, सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। ज्योतिषीयों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1 करोड़ 85 लाख 58 हजार 112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6.03 बजे हुआ था।

शनि कृपा के लिए आजमाएं ये सात उपाय

शनिवार का व्रत करने वाले शनिभक्त को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि-विधान से पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं।

» शनिदेव वैसे तो अपनी पूजा मात्र से ही खुश हो जाते हैं पर आप कुछ अन्य उपाय आजमाकर शनिदेव की कृपा के अनुयायी बन सकते है।

» शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की पूजा भी करनी चाहिए।

» शनि भक्त इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनि देव के नाम से दीप प्रज्वलित करना चाहिए।

» शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधो एवं जाने-अनजाने जो भी आपसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर सात बार परिक्रमा करनी चाहिए।

» शनि की शांति के लिए नीलम को तभी पहना जा सकता है।

» शनिश्वर के भक्तों को संध्याकाल में शनि मंदिर में जाकर दीप भेंट करना चाहिए और उड़द दाल में खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद लेने के पश्चात आपको प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खाना चाहिए।

» काली चीटियों को गुड़ एवं आटा देना चाहिए।

प्रेरक प्रसंग

मेहनत की कमाई

काशी में एक कर्मकांडी पंडित का आश्रम था, जिसके सामने एक मोची बैठता था। वह जूतों की मरम्मत करते वक्त कोई न कोई भजन गाता रहता था लेकिन पंडितजी का ध्यान कभी भी उसके भजन की तरफ नहीं जाता था।

एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उस समय उनका ध्यान मोची के भजनों की तरफ गया। पंडित जी का मन रोग की तरफ से हटकर भजनों की तरफ चला गया। धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ, कि जूते गांठने वाले के भजन सुनते-सुनते उनका दर्द कम हो रहा है।

एक दिन एक शिष्य को भेजकर उन्होंने मोची को बुलवाया और कहा 'भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मेरा रोग बड़े-बड़े वैद्यों के इलाज से भी ठीक नहीं हो रहा था लेकिन तुम्हारे भजन सुनकर मैं ठीक होने लगा हूं।'

उन्होंने उसे सौ रुपये देते हुए कहा 'तुम इसी तरह गाते रहना।' रुपये पाकर मोची बहुत खुश हुआ। लेकिन पैसा पाने के बाद से उसका मन कामकाज से हटने लगा। वह भजन गाना भूल गया। दिन-रात यही सोचने लगा कि रुपये को संभालकर कहां रखे। काम में लापरवाही के कारण उसके ग्राहक भी उस पर नाराज रहने लगे।

धीरे-धीरे उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी। उधर भजन बंद होने से पंडित जी का ध्यान फिर रोग की तरफ जाने लगा। उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक मोची पंडित जी के पास पहुंचकर बोला 'आप अपने पैसे वापस रख लीजिए।' पंडित जी ने पूछा 'क्यों, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा?' मोची बोला 'कहा तो नहीं, लेकिन इन पैसों को अपने पास रखूंगा तो आप की तरह मैं भी बिस्तर पकड़ लूंगा। इसी रुपये ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा गाना भी छूट गया। काम में मन नहीं लगता, इसलिए कामकाज ठप हो गया। मैं समझ गया कि अपनी मेहनत की कमाई में जो सुख है, वह पराये पैसों में नहीं है। आपके धन ने तो परमात्मा से भी नाता तुड़वा दिया।

यातायात जाम, संकेतक, खराब सड़कें देश का 20% पेट्रोल बर्बाद करते हैं

पालिकायें, निगम व पुलिस का उद्देश्य

जनता को हैरान कर लूटना....

परिवहन विभाग को जनता की परेशानी नहीं अपनी लूट से मतलब

पूरे देश में प्रतिदिन 10000 से ज्यादा दुर्घटनाओं में लगभग 2000 लोक दुर्घटना का शिकार होकर मर जाते हैं। पर ना केंद्र सरकार वह ना राज्य सरकार को कोई मतलब है, इससे। उन्हें तो मोटी कमाई के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की सड़कें पुल व फ्लाई ओवर जल मोदी के मित्र अदानी को ठेके पर देकरमोटी कमाई करनी है। से मतलब है।

सारे भ्रष्टों और जालसाजों को मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर केंद्रीय व राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, व उसके सड़क डकैती निगमों के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी राज्यों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं पालिकाओं निगमों के इंजीनियरों को यातायात के दबावों को देखते हुए सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य को अत्यंत गंभीरता भविष्य को ध्यान में रखकर पूरा करना चाहिए ताकि लोग व वाहन चालक सुगमता से जीवन की यात्रा पूरी कर सकें।

परंतु यहां तो हर किसी का उद्देश्य अपनी मोटी कमाई के लिए जानबूझकर ऐसे काम करना ताकि जनता परेशान होट्रैफिक जाम हो लड़ाई झगड़े दुर्घटनायें हों और उसकी आड़ में यह पुनः निर्माण तोड़फोड़ करने नाली, जलापूर्ति केवल बिछाने के लिए तोड़फोड़ व मरम्मत करने यातायात सुधारने आदि के नाम पर बार-बार सड़कों पर मोटी कमाई करने जनधन खर्च करते रह सके और जनता परेशान होती रहे। इसमें देश का लगभग 20% पेट्रोल और विदेशी मुद्रा जो पेट्रोल डीजल गैस के आयात पर खर्च की जाकर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने के साथ बर्बाद होती है। जबकि यातायात पुलिससनगर निगम पालिकाएंऔर सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी अंबेडकर चाहें तो इस 20% को घटा कर 3 से 5% पर ला सकते हैं। जिससे जनता का धन बचने के साथ सरकार का भी धन बचने के साथ पर्यावरण में फैलते प्रदूषण को रोकने में भीसहायक होगा। डमरू पालिकाओं और निगमन में जितने भी संकेतक लगे हुए हैं उन्हें केवल कुछ सेकेंड की सेटिंग करने से निर्बाध यातायात को बिना रूके बिना पेट्रोल डीजल के धुआं उड़ाए बर्बाद किये सुगमता से एक छोर से दूसरे छोर तक निकाला जा सकता है। जिससे दुर्घटनाएं भी कम होगीसंकेत पर हर चौराहे पर कम से कम जाम लगेंगे दूसरी तरफ जो तिराहे हैं जिस तरह पर दाएं या बाएं जब एक आधी सड़क को सीधे जाने वालों के लिए खोला जा सकता है तो उसे पर बार-बार रोकने की जरूरत क्या है हर तरह पर सीधी जाने वालों के लिए बिना रुके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए परंतु जानबूझकर यातायात पुलिस हर तरह पर भी सीधे जाने वालों को भी रोकते हैं। जिससे जाम भी लगते हैं। पेट्रोल डीजल गैस भी ज्यादा बर्बाद किया जाता है।

दूसरी तरफ किसी भी चौराहे पर संकेतक को 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दिया जाना चाहिए ताकि हर तरफ के लोगों को बराबर अवसर मिलता रहे परंतु इंदौर में अनेकों चौराहों से 5 और 6 राह वाले मार्गों पर 40 50 सेकंड तक समय देकर दूसरे वाले का नंबर ढाई तीन मिनट बाद तक भी आता है। इससे लोग मजबूरी में सिग्नल तोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर यहां यातायात पुलिस की पद स्थापना और नियुक्ति का उद्देश्य मोटा धन लेकर मोटी कमाई के लिए जान बूझकर लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए विवश किया जाए और फिर उसको नींबू कानून में उलझा उससे वसूली की जाए। ही होता है जैसा कि मैं इसलिए समाचार पत्रों में स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार के परिवहन के पंजीयन अनुज्ञप्ति अंतरण पुनः पंजीयन आदि के शुल्क मध्य प्रदेश के शुल्कों मात्र 10% हैं

(शेष पेज 6 पर)

180 दिन काम के 405 दिन का वेतन 900 घंटे काम

खोलो हर शनिवार को सभी शासकीय कार्यालय

आम आदमी 3650 घंटे काम करता है। मुश्किल से रोजी रोटी मिल पाती है

मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद से सभी शनिवारों को कार्यालय बंद रखने लगे। जिन्हें तत्काल खोल जाना चाहिए। क्योंकि सरकार ने सुबह 10:00 बजे से शाम को 6:00 तक के लिए कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया था। और कोई भी कार्यालय मध्य प्रदेश सभी सरकारी कार्यालय गांव की पंचायतों से लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल तक के मंत्रालयों के कार्यालय तक 11:00 बजे खुलते हैं। अधिकांश कर्मचारी 11:30 बजे तक आते हैं और महिलाएं चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी 12:30 बजे तक आती हैं। कार्यालय अवश्य 10:30 बजे तक खुलते हैं। और शाम को 5:00 बजे तक अधिकांश कार्यालय बंद हो जाते हैं। तो आखिर जनता के पैसे की इस तरह की बर्बादी क्यों? जबकि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को 52 रविवार 52 शनिवार के भी 18 से 20 दिन की अलग-अलग छुट्टियां होती हैं। जो कुल 122 दिन हो गई। अर्थात 4 महीने की यही छुट्टियां हो जाती है।

इसके साथ हर कर्मचारी को 13 आकस्मिक अवकाश, 33 अर्जित अवकाश, 15 चिकित्सा अवकाश मिलते हैं। कुल 61दिन का सवैतानिक पूरा वेतन मिलता हैं। अर्थात दो माह का वेतन अतिरिक्त मिलता है। जहां तक शिवराज सिंह का सवाल वह तो पुराना रेती का तस्कर है। उसने जानबूझकर इसलिए शनिवार रविवार की छुट्टी करवाई थी। ताकि 48 घंटे तक उसके 700 से ज्यादा डंपर बुदनी होशंगाबाद के नर्मदा के किनारों से रेती का अवैध खनन कर बेचने में कोई परेशानी न हो।

कांग्रेस ढाई सौ से ज्यादा वस्तुओं पर वेट लगाने पर भाजपा भारी आंदोलन करते थे जबकि वर्तमान मेंराज्यों में और केंद्र कीसरकारों ने 1500 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी ठोक दिया गया। और जनता से लूटा हुआ पैसा सरकार कर्मचारियों अधिकारियों पर कैसे पैसा उठाती है जबकि एक आम आदमी को 365 दिन में से 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करना पड़ता है उसके बावजूद भी उसके पास दो वक्त की रोटी बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा बिजली का बिल भरने के लिए नहीं कमा पाता। बेशक सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार भारी तकलीफ दे रही है पर ये छुट्टियों के संबंध में सरकार को ध्यान देना चाहिए और हर शनिवार को कार्यालय खोले जानी चाहिए। क्योंकि वैसे भी पिछले 20 सालों से भर्ती है ना होने, सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने व मृत्यु के कारण के कारण सभी सरकारी विभागों में 20-30% अधिकारी कर्मचारी बचे हैं। इसलिए आवश्यक है की हर शनिवार को कार्यालयों को खोला जाना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादक: अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958